RAJYA SABHA

Tuesday, the 24th July, 2001/2 Sravana, 1923 (Saka)
The House met at eleven of the clock, Mr. Chairman in the Chair.

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

*21. [The questioner (Shri Rumandla Ramachandriah) was absent. For answer vide page 35 infra]

Report of the Bimal Julka Committee on Charki Dadri Air Crash

- *22. SHRI R.P. GOENKA: Will the Minister of CIVIL AVIATION be pleased to state:
- (a) whether it is a fact that the report of the three member Bimal Julka Committee which investigated the Charki Dadri air crash and reportedly made some far reaching suggestions on the functioning of the Air Traffic Control, in 1997 has been shelved in India while a neighbouring country has already accepted and implemented its recommendations;
- (b) if so, the details of the major recommendations made by the Committee and the action taken thereon; and
- (c) the reasons for rejection or delay in implementing each of the recommendations?

THE MINISTER OF CIVIL AVIATION (SHRI SHARAD YADAV): (a) to (c) A Statement is laid on the Table of the Sabha.

Statement

Regarding Report of the Bimal Julka Committee on Charki Dadri
Air Crash

- (a) to (c) Bimal Julka Committee did not investigate the Charki Dadri air crash which was investigated by Justice R.C. Lahoti Committee. No information available about acceptance and implementation of Julka Committee recommendations by any neighbouring country. Bimal Julka Committee was set up with the following terms of references:—
 - (i) To examine the Cadre profile of Air Traffic Controllers (ATCOs) and to suggest the career progression/career plan.

- (ii) To sugest organisational structure of Air Traffic Management and
- (iii) To examine the remuneration profile.

The major recommendations of the committee were as follows:—

RECRUITMENT—For effective selection, psychological tests need to be introduced since the controllers must be above average in intelligence.

QUALIFICATION—Preference should be given to the commercial pilot licence holders/persons with basic knowledge of computers. Candidates should have proficiency in English and its pronunciation. Air Force personnel with ATC experience be considered for induction with specially modified training as Air Traffic Controllers.

TRAINING—Civil Aviation training units at Hyderabad and Allahabad should be reorganised/revitalised and there should be proper coordination. There should be proper ab-initio and On the Job-Training (OJT) programmes in accordance with the ICAO Regulations.

REORGANISATION OF ADMINISTRATIVE SET UP-At regional/field stations the level of supervision should be upgraded. Organisational structure for ATC should be overhauled.

CADRE PROFILE OF ATCOs—A cadre of "Executive ATCOs" should be created and such selected ATCOs should be eligible for special perks and previleges.

AIR SAFETY DISCIPLINE—AAI should have a separate Air Safety discipline reporting to Member (Ops.), AAI.

LICENSING & MEDICAL FACILITIES—The scheme of licensing and adherance to medical standards should be introduced. A system of periodic medical fitness checks should be introduced.

UNIQUE PROFESSION—Air Traffic Control has a uniqueness due to its very special nature which should be recognised.

JOB DEMANDS—Minimum basic services in the form of suitably furnished rest rooms should provided and working hours should be reduced.

REMUNERATION PROFILE—ATCOs should be given higher rating allowance, duty allowance, flight data processing allowance, On the Job Training (OJT) allowance, Civil Aviation Training Centre (CATC) allowance, Executive allowance, Stress allowance at the rates recommended for different categories of ATCOs.

Many of the recommendations regarding recruitment, training etc. have been accepted. Recruitment & Training is a continuous process and is being reviewed from time to time depending upon operational requirements.

The recommendation regarding licensing of ATCOs has been accepted and is being implemented in consultation with Directorate General of Civil Aviation (DGCA). As regards recommendation regarding remuneration profile, the rating allowance payable to ATCOs have been revised as recommended by Julka Committee w.e.f. 1.11.1997 from a total of Rs. 2400 p.m. to Rs. 9000 p.m. and in addition, stress allowance has also been increased from Rs. 800 p.m. to Rs. 4500/- p.m. Similarly, OJT allowance has been increased from 10% to 25% of basic pay and CATC allowance from 25% to 50% of basic pay. Further, ATC officers at CATC Allahabad are also entitled for 100% rating allowance.

However, recommendations in respect of the following have not been accepted by Airports Authority of India (AAI) due to its ramifications on other disciplines:

(i) Induction of commercial pilot license holders as ATC officers; (ii) Uniqueness of ATC profession; (iii) Reduction in working hours; and (iv) Cadre profile.

SHRI R.P. GOENKA: Sir, the answer given by the hon. Minister is only a part answer-one half of the answer and that also in one full page. It takes a lot of time to understand what he is trying to say. But nonethcless, we have understood it. It is, as I said, a part answer. I have two questions which have remained unanswered. The first question is: Why has the recommendation given by this

Committee that there should be licences for Air Traffic Control people on the same line as for the Pilots been rejected? The second question is: What steps have you taken for the betterment of air security and safety as recommended in the Report?

श्री शरद यादव: सभापति जी, माननीय सदस्य ने बिमल जुल्का कमेटी के बारे में सवाल पुछा है। मेरा इस बारे में यह कहना है कि यह मिनिस्ट्री की कमेटी नहीं है। एयरपोर्ट अधोरिटी ने अपनी एक इन्टरनल कमेटी बनाई थी। उसकी अधिकांश रेकमेंडेशन्स मान ली गई है। यदि आप कहें तो मैं सारी रेकमेंडेशन्स आपको बता देता हूं। उसकी केवल तीन मांगें नहीं मानी गई हैं। इसके पीछे एक लॉजिक है जो कि वाजिब बात है। नम्बर एक, वे कह रहे थे कि एट पार करके पायलट के बराबर हो। नम्बर दो, वे कह रहे थे कि उनके काम के वर्किंग आवर्स कम किए जाएं। नम्बर तीन, उनकी मांग थी कि वे एट आवर्स में जो काम करते हैं उस पर बेसिक पे का दो परसेंट दिया जाए। उनको दिए जाने वाले एलाउन्स इस कमेटी की रेकमेंडेशन्स पर हमने डबल कर दिए हैं। उनकी वाजिब मांगों के चलते एयरपोर्ट अधोरिटी पर 6 करोड़ रुपए का बर्डन आया है। इसके चलते दूसरे कांडर को भी हमने 25 करोड़ रुपए देने का काम किया। इसमें जितना संभव हो सकता था इनके साथ फेवर किया गया। आपको मालूम है कि 99 में जब हड़ताल हुई थी, उस हड़ताल के दौरान मेरे पास डिप्टी स्पीकर का भी लैटर है, हिन्दुस्तान में इस तरह की स्थिति पैदा हो गई कि हमारे पांच हजार घंटे खराब हुए, यानी पांच हजार आवर्स हमें एयर में बिताने पड़े और पयुअल भी काफी खर्च हुआ। हाई कोर्ट ने निश्चित तौर पर एक स्ट्रिकर दिया कि यह ठीक काम नहीं है, इसको तत्काल ठीक किया जाए। दूसरे, पूरे मीडिया ने कहा कि यह क्या हो रहा है। हमारे यहां ट्ररिस्ट का पीक सीजन था और ट्ररिस्टों का सब जगह डायवर्सन किया गया। उस पर एक्शन लिया गया। जुल्का कमेटी हमारे डिपार्टमेंट ने बनाई और हमने उनकी 9 मांगें पूरी कर दीं। इसके बाद वे जो मांग कर रहे हैं अगर उसे भी हम पूरा कर देंगे तो एयरपोर्ट अथाँ रिटी. जो एक प्रोफिट का कारपोरेशन है वह ढह जाएगा। इसलिए यह कहना कि हमने आप लोगों को उत्तर नहीं दिया, ऐसा नहीं है। जो तीन रिकमेंडशन्स है उन्हें माना नहीं जा सकता।

भी आर**्पी॰ गोयनकाः सभापित जी, मेन स**वाल यह उठता है कि सेफ्टी के लिए जुल्का कमेटी ने जिन रिकमेंडेशन्स की बात कही थी उन्हें माना गया है या नहीं माना गया है। अगर नहीं माना गया है तो क्यों नहीं माना गया है?

श्री शरद यादव: सभापति जी, सेफ्टी के बारे में जो रिकमेंडेशन्स दी गई थीं उन्हें मान लिया। गया है और डी॰जी॰सी॰ए॰ उस पर काम कर रहा है।

SHRI PREM CHAND GUPTA: Sir, whether the Julka Committee

looked into the Dadri air mishap or not is a separate question. The thing is that our airspace is the most unsafe airspace in the world. Most of the large aircrafts are equipped with the T-CAS System, whereas the military aircraft and small aircraft are not fitted with this system. How is the co-ordination taking place? We have air mishaps on the ground; we have air mishaps in the sky, but nothing is being done. When there is no co-ordination between the systems, when there is no compatibility with each other, how can air safety be ensured?

श्री सभापति : नहीं, यह हो गया है।

श्री शरद यादव: सभापित जी, इस सवाल में जुल्का कमेटी के बारे में पूछा गया है। माननीय सदस्य ने कहा है कि चरखी दादरी के इलाके में पोल्युशन हो गया था। लाहोती कमीशन ने बारह महीने में पंद्रह रिकमेंडेशन्स दी थीं, इन पन्द्रह में से अधिकांश मान ली गई हैं और जो दो-तीन नहीं मानी गई हैं उनका वास्ता भी ए॰टी॰सी॰ से है। इसी तरह की उल्टी-सीधी मांगें उसमें की गई हैं। रहा सवाल माननीय सदस्य का तो माननीय सदस्य गुप्ता जी ने जो पूछा है में उससे एग्री हूं और हम उसे डिफेंस के साथ परस्यु कर रहे हैं। हमने लाहोती कमीशन के बाद जितने भी हिन्दुस्तान के डोमेस्टिक जहाज हैं, एयर लाइंस हैं, इंडियन एयर लाइंस हैं, एयर इंडिया हैं, जैट है और जितने प्राइवेट एयर लाइंस हैं उनमें आकाश इंस्ट्रूमेंट, जो एक्सीडेंट एवोइडिंग इंस्ट्रूमेंट है सब में लगा दिया गया है और हमारी बातचीत...(व्यवधान)...

श्री प्रेमचन्द गुप्ताः उसमें एयर लाइंस के जितने जहाज हैं There are two thousand flights a day—small aircraft and flights of the Air Force—and there is no co-ordination. सब भगवान भरोसे चल रहा है।

श्री शरद यादवः नहीं, नहीं सभापति जी, मैं कह रहा हूं कि हम डिफेंस के साथ परस्यु कर रहे हैं और वे एग्री हो रहे हैं। वे इस बात पर एग्री हो रहे हैं और इस पर काम चला हुआ है। मैं आपकी बात मानता हूं कि यह सेपटी का मामला तब तक पूरी तरह से मुकम्मिल नहीं हो सकता जब तक हमारा डिफेंस के साथ को-ऑर्डिनेशन और एयर सेपटी का मामला ठीक से एडजस्ट नहीं होता।

श्री सतीश प्रधानः सभापति जी, मैं आदरणीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा, जैसा कि आपने अभी लाहोती कमीशन का जिक्र किया उसमें दो नम्बर पर सिफारिश थी कि सार्थक कमींदल संसाधन प्रबंधन (सी॰आर॰एम) संबंधी कार्यक्रम को कमींदल प्रशिक्षण का एक अभिन्न अंग बनाया जाना चाहिए और किसी पायलट को पायलट इन कमांड के रूप में नियुक्त करने से पहले यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि उसमें सी॰आर॰एम॰ कौशल तथा नेतृत्व संबंधी सभी गुण विद्यमान है। जो यह सूचना दी गई थी क्या उस पर सब जगह अमल होना शुरू हो गया

है; मैं सिर्फ इंडियन एयर लाइंस और एयर इंडिया की बात नहीं कर रहा हूं। हमारे हवाई क्षेत्र का प्रयोग विदेशी कंपनियों के जहाज भी करते हैं। क्या उनके पायलट इस विषय में सक्षम हैं?

भी शरद यादवः सभापति जी, इस सवाल से यह सवाल उठता नहीं है फिर भी मैं इसका जवाब देना चाहता हूं।

मी सतीश प्रधान: कैसे नहीं उठता है, आपका हवाई क्षेत्र जिस तरह से खुला है....

श्री शरद यादवः मैं आपको जवाब दे रहा हूं, मैं बता रहा हूं। आपने जो सवाल किया है इसके उत्तर में मैं यह कहना चाहता हूं कि लाहोती कमीशन की जो रेकमन्डेशंस थीं, उसमें एक महत्वपूर्ण रेकमन्डेशन यह भी और उस के आधार पर हम अपने क्रू और जो पायलेट हैं, उनके मामले को ''एकाव'' में ले गए। चरखी दादरी का जो कांड हुआ, जो काल्यूजन हुआ वह लैंग्वेज प्राबलम से हुआ। हमारे ही देश से पहली बार यह बात हुई कि इस लैंग्वेज प्रावलम का समाधान किया जाना चाहिए। इसके लिए यह किया गया कि जो भी पायलट हों उनको इंग्रलिश लैंग्वेज और इंग्रलिश के प्रोनंसिएशन की ठीक जानकारी होनी चाहिए। वह जो कांड हुआ था वह निश्चित तौर से लैंग्वेज प्राबलम के कारण हुआ था। क्रू तथा पायलेट की लीडरिशप क्वालिटी के बारे में जो रेकमन्डेशंस हुई है उन पर हम बाकायदा ध्यान दे रहे हैं। उनको हमने एक्सेए किया है। इन सारी बातों पर हमारा सारा काम चला हुआ है।

श्री संतोष बागड़ोदियाः समापित जी, मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं, अभी अभी मंत्री महोदय ने कहा कि एयरपोर्ट अथारिटी एक प्रोफिट मेकिंग आर्गनाइजेशन है और अगर हम सारी किमन्डेशंस को मानकर चलें तो हमारा भट्टा बैठ जाएगा। भट्टा यात्रियों का बैठेगा या एयरपोर्ट अथारिटी का बैठेगा मुझे पता नहीं। महोदय ये सेक्युरिटी कम्मोमाइज की बात कर रहे हैं। एक बार ऐसा भी हुआ—जैसे कि अभी भाषा के बारे में बताया गया, उजबेगिस्तान का जो पायलट था, उसका एक्सीडेंट सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि उसको अंग्रेजी नहीं आती थी, क्या आपने यह तय किया है कि बाहर से जो हवाई जहाज यहां आयेंगे उनके पायलटों को अंग्रेजी का कंपलसरी ज्ञान होगा? अगर ऐसा है तो क्या आप इस बारे में यह आश्वासन देंगे कि आप कास्ट फैक्टर पर ज्यादा ध्यान नहीं देंगे। कास्ट की बात बाद में आएगी लेकिन पहले आप सेक्युरिटी की ओर आप ध्यान देंगे? आप हर चीज में रेट बढ़ाते जा रहे हैं। अभी अभी आपने टैक्स बढ़ाया है। एयरपोर्ट टैक्स आपने बढ़ा दिया है। लेकिन कम से कम हमारे जो एम॰पीज हैं, जो रोज ट्रैक्त करते हैं, कम से कम अप इमें सैटिस्फैक्शन दिलाइए कि इम जो यहां के जहाजों में ट्रैक्त कर रहे हैं। हमें जैसे सारी दुनिया में सेक्युरिटी होती है, उससे अच्छी सेक्युरिटी है यहां मिल रही है और भविष्य में सेक्युरिटी और आपकी लापरवाही के कारण यहां कोई एक्सीडेंट नहीं होगा, यह आश्वासन आप यहां पर दीजिए?

श्री शरद यादव: मैंने अपने उत्तर में यह कभी नहीं कहा कि हम सेपटी के साथ कोई कम्प्रोमाइज कर रहे हैं। जो बिमल जुल्का कमेटी है उसकी रेकमन्डेशंस को हमने इतनी दूर तक माना है कि जो एलाउन्सेज हैं, वह हमने दुगुने कर दिए हैं। जो जुल्का कमेटी की रेकमन्डेशंस हैं, उससे हमारे ऊपर 6 करोड़ रुपए का बर्डन पड़ा है। पहले एरोड्रम कंट्रोलिंग रेटिंग का हम 200 रुपए देते थे, अब उसको दो हजार दे रहे हैं।....(क्यवधान)...सुन तो लीजिए...

भी संतोष बागड़ोदिया: आप गुस्सा क्यों कर रहे हैं?

श्री शरद यादवः मैं गुस्सा नहीं कर रहा हूं। मुझे जुकाम हुआ है, इसिछए थोड़ी आवाज ज्यादा है। मैं गुस्सा नहीं हो रहा हूं। लेकिन जैसे मैंने आपकी बात को शांति से सुना आप भी मेरी बात शांति से सुन लीजिए।

एरिया केंद्रोल रेटिंग एलाउन्स जो 400 रुपया था उसको हमने दो हजार कर दिया है। ओजीटी जो बेसिक पे का 10 परसेंट था, उसको हमने 25 परसेंट कर दिया है। जो सीएटीसी इलाहाबाद है, उसमें हम पहले बेसिक पे का 25 परसेंट देते थे, उसको हमने 50 परसेंट कर दिया है। इसी तरह से जो स्ट्रेस एलाउन्स है, उसको 25 परसेंट से लेकर 50 परसेंट बढ़ा दिया है। पहले 800 रुपया देते थे अब 4500 रुपए देते हैं। लाइव डाटा प्रोसेसिंग एलाउन्स पहले कुछ नहीं देते थे अब एक हजार रुपए देते हैं। इस तरह से 6 करोड़ रुपए का बर्डन हम अपने ऊपर ले रहे हैं। इसलिए हम सेफ्टी के साथ कोई कम्प्रोमाइज कर रहे हैं, इसका कोई सवाल ही नहीं है।

श्री नरेन्द्र मोहनः सभापित जी, मंत्री जी ने जो बातें कही हैं इनमें विचारणीय बात यह है कि मंत्री जी का कहना है कि प्रतिरक्षा विभाग के साथ उनके मंत्रालय का समन्वय नहीं हो पा रहा है। मैं जानना चाहता हूं कि वास्तविकता क्या है? क्यों ऐसी स्थिति है जिस के कारण प्रतिरक्षा मंत्रालय के साथ आपके मंत्रालय का समन्वय नहीं हो पा रहा है? हमारा आकाश असुरक्षित क्यों है?

श्री सभापतिः वह कहते हैं मैंने कहा ही नहीं। ...(व्यवधान)...

श्री नरेन्द्र मोहनः यह कहा है कि डिफेंस के साथ हमारे कोआर्डिनेशन नहीं हो पा रहा है। कोआर्डिनेशन का अर्थ होता है समन्वय। मंत्री जी ने कहा कि समन्वय नहीं हो पा रहा है। ... (व्यवधान)... मैं प्रश्न पूरा कर लूं मंत्री जी। मैं जानना चाहता हूं कि वैमानिक सुरक्षा के संबंध में जो भी आश्वासन समय-समय पर संसद् में दिये गये हैं, उनमें से आपने कितनों की पूर्ति कर ली है और कितने आश्वासनों की पूर्ति नहीं हो पाई है? आए दिन विमान दुर्घटनामस्त होने की संभावनाएं उत्पन्न हो जाती हैं। आपने कहा कि भारतीय विमान आधुनिकतम उपकरणों से सुसज्जित हैं, क्या आप बता सकते हैं कि कितने भारतीय विमान ऐसे हैं जो उड़तें हैं जहां आधुनिकतम सुरक्षा संबंधी प्रावधान नहीं हैं। आपके विमान पत्तनों पर आधुनिकतम विमानों के लैंडिंग और एवियेशन की सुविधाएं भी नहीं हैं। दिल्ली जैसे एयरपोर्ट पर अनेक समस्याएं हैं, उनके बारे में आप क्या निराकरण कर रहे हैं? क्या आप यह बता सकेंगे?

श्री शरद यादव: सभापित जी, माननीय सदस्य ने जो कहा है कि मैंने कहा कि कोई कोआर्डिनेशन नहीं है। मैंने साफ-साफ यह बात कही है कि हमारी डिफेंस के साथ चर्चा हुई है और सहमित भी बन गई है, हमारा कोआर्डिनेशन चला हुआ है और निश्चित तौर पर दो विभागों में जब चर्चा चलती है तो चाहे वह डिफेंस हो या कोई और विभाग हो, डिफेंस ज्यादा सेंसेटिव मामला है और जहां तक सेफ्टी का मामला है, सेफ्टी के संबंध में हमने जितने कदम उठाए हैं, जितने काम किये हैं, जितना एडवांस किया है, उसमें किसी भी तरह का कोई कम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाता है। सिविल एवियेशन सेफ्टी के लिए लिये गये स्टेप्स हैं लाइव डाटा रिकार्डिंग की अब 100 परसेंट मोनिटरिंग होती है। इससे पाइलट या ए॰टी॰सी॰ की गलती तुरंत पकड़ी जाती है। मिनिमम सेफ एल्टीट्यूड वार्निंग सिस्टम ...(व्यवधान)...।

श्री नरेन्द्र मोहनः यह बाद में होता है। मंत्री जी, क्या आपके विमानों में यह सारी सुविधाएँ हैं? ...(व्यवधान)...

श्री शरद यादव: सभापित जी, जो पटना में एयर क्रैश हुआ उसमें लास्ट आवर तक इंस्ट्रूमेंट वार्निंग सिस्टम में यह बाकायदा रिकार्ड पर है बाकायदा वार्निंग दी कि यह नीचे आ गया है इसको ऊपर ले जाओ, । ऊपर ले जाओ । आप तो बात कह रहे हैं कि इसका कोई अर्थ नहीं निकलता है, ऐसी बात नहीं है। मिनिमम सेफ एल्टीट्यूड वार्निंग सिस्टम का प्रोविजन कर दिया है जिसमें ए॰टी॰सी॰ को वार्निंग मिल जाती है कि एयरक्राफ्ट सेफ लाइट से नीचे उतर रहा है, ए॰टी॰सी॰ पायलट को एलर्ट कर देता है। मेसेज रिकार्डिंग राडार लगाए गए हैं जिससे पूरे देश का एयर स्पेस कवर हो गया है। ए॰सी॰एस॰ मेंडेटरी कर दिया गया है जिससे दो हवाई जहाजों को पास आने यानि आकाश में वार्निंग मिल जाती है और वह सब में लग चुका है। बाकी जो देश की दूसरी एयरलाइंस हैं उनके ऊपर हमारा बस नहीं है लेकिन हम उनके साथ भी इस बात को परस्य कर रहे हैं।

UTI's suspension of US-64 Scheme

@*23. SHRI V.V. RAGHAVAN:†
SHRI N.R. DASARI:

Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the UTI suspended redemptions and sale of its US-64 Scheme on 2nd July, 2001, affecting over 10 million investors;

[@] Question Nos. 23, 33 and 38 were taken together.

[†] The question was actually asked on the floor of the House by Shri V.V. Raghavan.